NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

M.P.S.-4

तुलनात्मक राजनीति : मुद्दे और प्रवृत्तियाँ

(Comparative Politics : Issues and Trends)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Radheyshyam Chaurasiya*

NEERAJ
PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 450/-

Content

तुलनात्मक राजनीति : मुद्दे और प्रवृत्तियाँ

(Comparative Politics: Issues and Trends)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1-5
Question Paper—December-2023 (Solved) 1-6
Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2
Question Paper—December-2022 (Solved) 1-4
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-8
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-5
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1-6
Question Paper—December, 2019 (Solved) 1-3
Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-3
Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-4
Question Paper—June, 2018 (Solved) 1
Question Paper—December, 2017 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2017 (Solved) 1-5

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	तुलनात्मक राजनीति : स्वरूप, महत्त्व और विकास	1
2.	तुलनात्मक दृष्टिकोण और प्रणालियाँ : व्यवस्था, संरचना और सार्वजनिक नीति	7
3.	तुलनात्मक दृष्टिकोण : राजनीतिक अर्थव्यवस्था, निर्भरता और विश्व व्यवस्थाएँ	19
4.	राज्य के सिद्धान्त	22
5.	विकासशील समाजों में राज्य : एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी अनुभव	35
6.	राज्य-नागरिक समाज सम्बन्ध : उभरते हुए प्रतिमान	41
7.	भूमण्डलीकरण और राज्य	44

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

8. क्षेत्रीय संगठन और राज्य 47
9. अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राज्य 50
10. संक्रमणकालीन बहुराष्ट्रीय निगम और राज्य 60
11. राष्ट्रवाद : विभिन्न दृष्टिकोण 62
12. राष्ट्रवाद के स्वरूप 65
13. उपनिवेशवाद और उपनिवेश-विरोधी आंदोलन 68
14. राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय 72
15. राज्य निर्माण व संविधानवाद 84
16. संजातीयता राजनीति तथा राज्य 119
17. समुदाय पहचान की राजनीति 122
18. संजातीय आन्दोलन 130
19. राजनीतिक शासन प्रणाली 140
20. नौकरशाही 170
21. राजनीति में सेना 176
22. संघवाद : प्रतिमान और प्रवृत्तियाँ 182
23. राजनीतिक दल एवं दलीय पद्धति 192
24. हितबद्ध समूह, दबाव (प्रभावक) समूह तथा लॉबिंग 205
25. निर्धनता व मानव विकास 215
26. सामाजिक लिंगभेद और विकास 220
27. पर्यावरण 226
28. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राजनीति 228
29. विकेन्द्रीकरण तथा सहभागिता 231
30. मानवाधिकार 234

Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

तुलनात्मक राजनीति : मुद्दे और प्रवृत्तियां

M.P.S.-4

(Comparative Politics – Issues and Trends)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम* **दो** *प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

खण्ड-I

प्रश्न 1. विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की धारणा और राजनीतिक विश्लेषण के लिए इसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-20, 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण मुद्दे', 'निर्भरता की अवधारणा का पूर्वानुमान', 'निर्भरता सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं विश्व व्यवस्था के रूप में पूँजीवाद', 'विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की आलोचना' तथा पृष्ठ-21, प्रश्न 1

प्रश्न 2. वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–वैश्वीकरण, राष्ट्रवाद और उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन में विद्वानों के बीच बहस का विषय रहे हैं। दोनों अवधारणाओं का हमारे समकालीन विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका महत्त्व आधुनिक समाजों और राष्ट्र-राज्यों के निर्माण में निहित है और एक ऐसी दुनिया में उनकी भूमिका है, जिसमें परस्पर निर्भरता बढ़ी है। वास्तव में, राष्ट्रवाद को इस दुनिया में जीवित रहने में बहुत कठिनाई हुई है और कुछ लोग तर्क देंगे कि यह कम महत्त्वपूर्ण हो गया है। हालांकि अन्य लोग कहेंगे कि राष्ट्रवाद वैश्वीकरण से लाभान्वित हो रहा है और पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। इसलिए, राष्ट्रवाद पर वैश्वीकरण के प्रभावों का पता लगाने और उनके संबंधों को संबोधित करने के लिए, यह निबंध वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को देखने जा रहा है, दोनों अवधारणाएँ एक-दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती हैं और इस परस्पर क्रिया के प्रमुख पहलू क्या हैं।

वैश्वीकरण को व्यापार, संचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में बाधाओं को खत्म करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज की दुनिया पहले की तुलना में बहुत अलग हो गई है। प्रौद्योगिकी और संचार में प्रगति के साथ, दुनिया विजातीय हो गई है, भूगोल की बाधाएँ कम हो गई हैं और दुनिया अधिक एकरूप और एकीकृत हो गई है। वैश्वीकरण के सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हुए, कुछ लोग इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं, जो दुनिया भर के विभिन्न जातीय समूहों की विरासत और संस्कृति को नष्ट कर देती है। उनके लिए, वैश्वीकरण एक दुःस्वप्न है, जो वर्तमान में हो रहा है और पीढ़ियों तक जारी रहेगा।

'राष्ट्रवाद' शब्द का अर्थ है एक राष्ट्र के सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति लगाव की भावना, तथा एक राष्ट्र में अपने प्रति गर्व की भावना। राष्ट्रवाद अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है, जिसका उपयोग किसी विशेष संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने और उसका बचाव करने के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रवाद का एक उदाहरण तब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर चला जाता है, फिर भी अपने देश की खेल टीमों का उत्साहवर्धन करता है और स्थानीय समाचारों से अपडेट रहता है। राष्ट्रवाद आधुनिक समाज और सामाजिक एकजुटता की नींव है; इसका उपयोग राजनेता राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए भी करते हैं। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि ने राष्ट्र-राज्य की स्थापना की, जिसकी सदस्यता आधुनिक समाज का आधार बनी। राष्ट्रवाद को उन राज्यों का लक्ष्य घोषित किया जाता है, जो अपने उद्देश्यों के समर्थन में जनमत को प्रेरित करने के लिए शांति या युद्ध में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

जब वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की बात आती है, तो यह कहा जा सकता है कि इस संबंध को संबोधित करने वाले तीन प्रमुख तर्क हैं। पहला तर्क कहता है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्रवाद को कम कर दिया है, बढ़ती निर्भरता के माध्यम से और देशों के बीच राष्ट्रीय बाधाओं को कमजोर करके। इसके अलावा, समय और स्थान का संपीड़न लोगों को अधिक तेजी से बातचीत करने की अनुमति देता है, इस प्रकार राष्ट्रीय मतभेद गायब हो गए हैं या कम-से-कम कम महत्त्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य हो गए हैं।

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

तुलनात्मक राजनीति : मुद्दे और प्रवृत्तियां

M.P.S.-4

(Comparative Politics – Issues and Trends)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

***नोट :** प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

खण्ड-I

प्रश्न 1. उत्तर-उपनिवेशिक समाजों में 'राज्य के सिद्धांत' का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–साम्राज्यवादी राज्यों के अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, हॉलैण्ड, बेल्जियम आदि आते थे, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद साम्राज्यवादी राज्यों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और विकासशील राज्यों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत यूनियन के प्रभाव के अंतर्गत पूर्वी यूरोप के राज्य, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पौलेण्ड, बुल्गारिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लैटेविया और एस्टोनिया आदि आ गये, परन्तु 1990 के बाद न केवल उपर्युक्त राष्ट्र, बल्कि स्वयं यूनियन बिखर गया। अत: विश्व में विकासशील राज्यों के अंतर्गत विश्व के लगभग 180 देश आ गये।

जब ये देश स्वतंत्र हुए, तो इनकी दशा हर दृष्टि से शोचनीय थी। वहां निकृष्टता, दूषित जनस्वास्थ्य, बेकारी, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, संचार व्यवस्था, तकनीकी ज्ञान, बड़े उद्योगों और वैज्ञानिक ज्ञान आदि का अभाव था, अतएव स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही इन राष्ट्रों को इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। ये राज्य अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अपने विकास के कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें विकासशील राज्य या तृतीय विश्व के राज्य या नवोदित राज्य कहा जाता है।

इन देशों में कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और कहीं सैनिक तानाशाही है और कहीं एक दल का शासन है, कहीं एक व्यक्ति और उसके परिवार का शासन है। कई राज्यों में साम्प्रदायिकता की राजनीति का प्रभाव है। भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई है।

इन नवोदित राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता है और ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समाधान खोजना अत्यन्त कठिन है। इन देशों के समक्ष राष्ट्रीय एकता की भी समस्या है। इसके अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक विकास की भी समस्या है। विभिन्न देशों में सैनिक हस्तक्षेप करके सैनिक तानाशाही पर आधारित राज्य कायम कर लिया जाता है; जैसे–पाकिस्तान में पहले याकूब खां ने, फिर याहिया खां ने उसके बाद जिया-उल-हक ने अपना सैनिक शासन स्थापित किया और अब जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान में सैनिक शासन है। नवोदित देशों की प्रमुख समस्या यह है कि राजनीतिक दलों पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक दल का प्रभाव है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी दलों पर राजनीतिक घरानों का या नेताओं का प्रभाव है। कांग्रेस में नेहरू परिवार का, दलित जनों में मायावती व रामविलास पासवान का, अन्ना डी.एम.के. में जयललिता, डी.एम.के. में करुणानिधि का प्रभाव है। इसके अलावा अन्य दलों में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, चरण सिंह, देवीलाल आदि के घरानों का प्रभाव है और इन्हीं के परिवारों का शासन चलता चला आ रहा है। नवोदित देशों की अगली समस्या यह है कि यहां राजनीति में हिंसा का वातावरण छाया हुआ है तथा इसके अतिरिक्त निर्धनता, बेकारी और धन तथा सम्पत्ति के वितरण में अभूतपूर्व असमानता है; जैसे–भारतवर्ष में एक ओर खरबपति हैं, तो दूसरी ओर उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में निर्धनता के कारण भुखमरी फैली हुई है और भुखमरी के कारण मौतें हो रही हैं। यहां तक कि कृषक वर्ग भी आत्महत्या करने के लिए विवश है, अत: आतंकवाद का प्रचार हो रहा है। जम्मू-कश्मीर, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड आदि राज्य नक्सलवाद और आतंकवाद का शिकार हैं, जिनके कारण अशांति फैल रही है और इसी तरह अफ्रीका के विभिन्न देशों, नेपाल और लैटिन अमेरिका के देशों में कठिनाइयां हैं। अत: सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि विकासशील राज्यों के संबंध में राजनीतिक सिद्धांतों की अपेक्षा उनकी वास्तविक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्थिति व ऐतिहासिक परम्परा का अध्ययन आवश्यक है। इन राज्यों

NEERAJ PUBLICATIONS

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

तुलनात्मक राजनीति : मुद्दे और प्रवृत्तियाँ

तुलनात्मक राजनीति : स्वरूप, महत्त्व और विकास 1

NEERAJ PUBLICATIONS

प्रस्तावना

राजनीति सर्वव्यापी गतिविधि है। आरम्भ से ही एक राजनीतिक व्यवस्था की तुलना अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से की जाती रही है। किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके को सामान्यतया तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। मोटे तौर पर तुलनात्मक राजनीति का अर्थ व लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य प्रमुख राजनीतिक समस्याओं और विषमताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। यह समस्याओं व विभिन्नताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य है, जो विश्व की सरकारों और परिस्थितियों में प्रचालन करती हैं, उनको स्पष्ट करता है। सारांश रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्त्ता विभिन्न राज्यों के कार्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों और उसके अंतर्गत संस्थाओं एवं राजनीतिक दलों व दबाव समूह आदि का भी अध्ययन करता है।

तुलनात्मक पद्धति का अर्थ और विकास

राजनीतिशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राचीन समय से होता आया है। इस पद्धति का प्रयोग अरस्तू, सिसरो, पोलिबियस, मैकयावली, मान्टेस्क्यू, बेजहाट, सर हेनरीमेन, लॉर्ड ब्राइस और फाइनर जैसे अनेक विद्वानों ने किया है।

अरस्तू ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था और सर्वोत्तम संविधान के संबंध में निष्कर्ष निकाले थे। मान्टेस्क्यू ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी संविधान की तुलना करके शक्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। लॉर्ड ब्राइस ने पर्यवेक्षात्मक पद्धति के साथ-साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के तत्त्व बताये थे, तथा फाइनर ने भी तुलनात्मक पद्धति को अपनाया था।

परम्परागत दृष्टिकोण औपचारिक तथा वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। पर अब अध्ययन व्यापक रूप में किया जाता है और इसमें राजनीतिक दलों, संस्थाओं, दबाव समूह और आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यह विचार किया जाता है कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है और क्या परिवर्तन किया जाना चाहिएँ

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद 1950 के दशक में राजनीतिशास्त्र व्यावहारिक क्रान्ति द्वारा प्रभावित हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक व्यवस्था समाप्त हो गई और नये राज्यों का उदय हुआ, जिनका इतिहास, सामाजिक मान्यताएँ व राजनीतिक परम्पराएँ व अन्य विचार यूरोपीय देशों से भिन्न थे। अतएव तुलनात्मक राजनीति में अर्थव्यवस्था प्रकृति व सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक विकसित हो गई है। पर राजनीतिक व्यवस्थाओं में गठित तीव्र परिवर्तनों का विश्लेषण करने का प्रयास और इन्हें परम्परा से हटाकर आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास सफल रहा है। इस इकाई का दूसरा भाग तुलनात्मक प्रणाली की संभावना पर केन्द्रित है। परन्तु कुछ विद्वान इस तकनीकी कदम को मान्यता देते हैं। इसके बारे में कुछ व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं।

तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएँ

जिन वेलेन्डन के अनुसार राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों का अध्ययन है और उसने इनमें तीन बातों को महत्त्वपूर्ण माना है:

(i) विभिन्न देशों की विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अध्ययन।

(ii) राजनीतिक आचरण जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा मतदान प्रणाली का अध्ययन और आर्थिक अध्ययन आदि आते हैं।

(iii) विधि का अध्ययन।

एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनैतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक विवेचन तथा विश्लेषण करता है। एम. कार्टेज के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्त्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से क्या संबंध है, इसका अध्ययन करता है।

हैरी एक्टेन ने विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन उनका वर्गीकरण विकास क्रम तथा उनकी विभिन्नताओं और समानताओं को दिखाया है और उसका कहना है कि इसके अंतर्गत सम्पूर्ण मानव ज्ञान का इतिहास सम्मिलित है।

ब्रेबन्ती के अनुसार राजनीति सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के तत्त्वों की पहचान करती है और उन सबका अध्ययन करती है, जो राजनीतिक कार्योंखा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं।

मैकराइ्स और वार्ड की परिभाषा के अनुसार राज्य व्यवस्था के तीन अंग हैं–ऐतिहासिक परम्पराएँ, भौगोलिक तथा प्राकृतिक साधन, सामाजिक व आर्थिक संगठन, विचारधाराएँ, जीवन-मूल्य तथा राजनीति को संचालन करने की विधि तथा सरकार और शासन का ढांचा, तृतीय राजनीतिक दल, दबाव गुट तथा नेतृत्व का ढांचा आदि। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति में हम विभिन्न राज्यों, उनकी समस्याओं, उनकी संस्थाओं तथा सभी कार्यों व अंगों का सम्पूर्ण अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का अर्थ स्पष्ट करते हुए अरेण्ड लिपहार्ड ने लिखा है कि "*तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्त्यों को स्थिर रखते हुए, दो या अधिक परिवर्त्यों के बीच सामान्य आनुभाविक संबंधों की स्थापना करने की विधि है।*" आर्थर एल. कालबर्ग ने तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक रूप मात्र माना है। लासवेल और आल्मण्ड ने इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति मानते हुए लिखा है कि "*तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति से भिन्न हो ही नहीं सकती है।*" उनका मानना है कि तुलनात्मक पद्धति की भांति ही सामान्य नियमों के खोज के लक्ष्य की प्राप्ति की पद्धति है।

तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का अर्थ

राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक तरीका तुलनात्मक अध्ययन का तरीका भी है, जो बड़ा महत्त्वपूर्ण है। शासन व्यवस्थाओं तथा राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना तथा सिद्धान्त निश्चित करना, यह बात पूर्ण रूप से नवीन युग की देन नहीं है, बेशक आज इस पद्धति को बड़ा महत्त्व दिया जाता है। प्राचीन यूनान में राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाने वाले अरस्तू ने भी इसका प्रयोग किया था। उसने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इसके आधार पर अपने बहुत-से विचार निश्चित किए थे।

शासन का अर्थ है वह व्यवस्था, जो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति तथा पूर्ति करती है। शासन व्यवस्था में वैसे तो मुख्य रूप से तीन अंग–कार्यपालिका, विधानसभा तथा न्यायपालिका आते हैं, परन्तु इसके विस्तृत अर्थ लेते हुए इसमें संविधान, शासन तंत्र, राजनीतिक दल, अन्य औपचारिक संस्थाएँ भी सम्मिलित समझे जाते हैं। राजनीति का अभिप्राय साधारणत: उन सभी गतिविधियों से है जो शक्ति के नियंत्रण, निर्णय तथा नीति-निर्धारण तथा शक्ति के प्रयोग को प्रभावित तथा क्रियान्वित करती है। शासन और राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं से है। राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के लिए राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीति की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर लेना ही काफी नहीं है या यह जान लेना ही सब कुछ नहीं है कि किस देश में शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि विभिन्न देशों की शासन-व्यवस्थाओं तथा राजनीतिक कार्यप्रणालियों में क्या समानताएँ और असमानताएँ और वे क्यों हैं?

तुलनात्मक शासन तथा राजनीति की परिभाषाएँ (Definitions of Comparative Governments and Politics)

तुलनात्मक शासन तथा राजनीति की विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

1. **जीन ब्लोण्डेल** का कहना है कि "*तुलनात्मक शासन वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के विभिन्न प्रतिरूपों का अध्ययन है।*"

2. **एडवर्ड फ्रीमैन** के अनुसार, "*तुलनात्मक राजनीति शासन के विभिन्न रूपों तथा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है।*"

3. **ब्रेबन्ती** का कहना है कि "*तुलनात्मक राजनीति सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन कारकों या तत्त्वों की पहचान तथा व्याख्या है, जो राजनीतिक कार्यों तथा उनकी संस्थागत अभिव्यक्ति को प्रभावित करते प्रतीत होते हैं और जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए निश्चित कर लिए गए हैं।*"

4. **जी.के. रॉबर्ट्स** का कहना है कि "*तुलनात्मक शासन और राजनीति के अन्तर्गत हम राज्यों, राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों का अध्ययन भी सम्मिलित है।*"

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

ऊपर दी गई विभिन्न परिभाषाओं में तुलनात्मक शासन तथा तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएँ भी हैं। इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलनात्मक शासन व राजनीति का विषय विभिन्न देशों में कार्यरत शासन प्रणालियों, राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रक्रियाओं तथा समस्त राष्ट्रीय व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण है।

तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का स्वरूप
(Nature of Comparative Government and Politics)

तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की प्रकृति के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है और इस आधार पर मुख्य रूप से दो विचारधाराएँ मान्य हैं:

1. लम्बात्मक तुलना अध्ययन तथा
2. अम्बरात्तीय अध्ययन।

1. लम्बात्मक तुलना अध्ययन (Vertical Comparison Study)–कुछ विद्वानों का विचार है कि तुलनात्मक शासन तथा राजनीति एक लम्बात्मक तुलना अध्ययन है। इसका अर्थ यह है कि इसके अन्तर्गत शासन तथा राजनीति, जो एक लम्बात्मक तुलना अध्ययन है, एक ही देश की शासन व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का नहीं। एक ही राष्ट्र में विभिन्न स्तरों पर शासन का संगठन होता है और राष्ट्रीय संस्थाएँ अपना कार्य करती हैं और राष्ट्रीय गतिविधियां चलती रहती हैं जैसे कि राष्ट्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारें और इनका परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। एक ही देश की सरकार की दूसरे देश की सरकार से तुलना नहीं की जाती।

परन्तु तुलनात्मक राजनीति के इस स्वरूप की काफी आलोचना हुई है। लगभग सभी देशों में शासन के विभिन्न स्तरों पर प्राय: एक-सी व्यवस्था मिलती है और उनमें तुलना करना संभव तथा व्यावहारिक और लाभप्रद नहीं हो सकता। तुलनात्मक राजनीति के लम्बात्मक अध्ययन दृष्टिकोण की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना हुई है:

(1) प्रशासन संचालन संबंधी समानता (Equality of Administration)–एक ही देश में, वहां चाहे एकात्मक शासन हो या संघात्मक शासन हो, सभी स्तरों की शासन-व्यवस्था लगभग समान होती है। सभी स्तर की सरकारों की कानून निर्माण प्रक्रिया, प्रशासन संचालन, सरकार का रूप, सरकार के अंगों का संगठन आदि बातें लगभग समान होती हैं सिवाय इसके कि राष्ट्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए यदि उनमें तुलना की जाती है, तो कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलने की संभावना नहीं रहती। इसलिए ऐसी स्थिति में लम्बात्मक तुलना का कोई लाभ नहीं होता।

(2) आर्थिक साधनों की समानता (Equality of Economic Resources)–एक ही देश में विभिन्न स्तरों की सरकारों के आर्थिक साधन लगभग समान होते हैं और आर्थिक साधनों का राष्ट्रीय संगठन तथा प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय सरकार के आर्थिक साधन अधिक व्यापक होते हैं और एकात्मक शासन प्रणाली में प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के आर्थिक साधन राष्ट्रीय सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं। दो सरकारों के आर्थिक साधन राष्ट्रीय सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं। दो सरकारों के आर्थिक साधनों में आधारभूत समानता न होने के कारण उनकी तुलना करना अर्थपूर्ण तथा लाभदायक नहीं होता।

(3) शक्ति की समानता (Equality of Power)–एक ही राष्ट्र में केन्द्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार की शक्तियाँ समान नहीं होती। केन्द्र के पास अधिक शक्ति होती है और उसे कार्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण करने पड़ते हैं। समस्त राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा अखण्डता की रक्षा करना, लोगों को बाह्य आक्रमण से बचाना, राष्ट्रव्यापी कल्याण योजनाएँ लागू करना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय सरकार के होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उसके पास अधिक शक्ति होती है और अधिक राष्ट्रीय सत्ता भी होती है। ऐसी शक्ति प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के पास नहीं होती। परिणाम यह होता है कि यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो परिणाम अर्थपूर्ण नहीं निकलते।

उपर्युक्त कारणों से तुलनात्मक राजनीति के लम्बात्मक तुलना अध्ययन की आलोचना हुई है और यह तुलनात्मक राजनीति के सही स्वरूप पर प्रकाश नहीं डालता। आज इस दृष्टिकोण को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है।

2. अम्बरात्तीय तुलना अध्ययन (Horizontal Comparison Study)–आधुनिक विचारक तुलनात्मक शासन व राजनीति की लम्बात्मक तुलना के स्वरूप से सहमत नहीं हैं और उन्होंने इसे अम्बरात्तीय तुलना अध्ययन बताया है। इसका अर्थ है–इसमें केवल राष्ट्रीय सरकारों तथा राजनीति की तुलना होती है। अत: तुलनात्मक शासन व राजनीति राष्ट्रीय सरकारों तथा राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन है। एक राष्ट्रीय सरकार की अपने ही राष्ट्र की किसी पुराने समय की राष्ट्रीय सरकार से तुलना हो सकती है तथा वर्तमान समय की या एक ही समय की विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना की जाती है। विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों में शासन संगठन, शासन संचालन, शक्ति, आर्थिक संसाधनों आदि के आधार पर आपस में काफी समानताएँ तथा असमानताएँ होती हैं। राष्ट्रीय सरकारों में ऐसे सामान्यीकरण संभव होते हैं, जिनके आधार

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

पर शासन संचालन तथा राष्ट्रीय व्यवहार को समझा जा सकता है, उनकी तुलना तथा विश्लेषण किया जा सकता है और अर्थपूर्ण निर्णय निकाले जा सकते हैं।

अम्बरात्तीय तुलना को दो भागों में बांटा जा सकता है:

(1) एक ही देश की विभिन्न समय की राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना तथा

(2) वर्तमान संसार में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना।

(1) देश की अपनी राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना (Historical Comparison of the National Governments within the Country)–किसी भी देश की वर्तमान शासन-व्यवस्था भूतकाल में घटी घटनाओं तथा प्रयत्नों का परिणाम होती है। उसे उसके अतीत से पूर्णत: अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वर्तमान सरकार उसकी संस्थाओं के संचालन तथा राष्ट्रीय गतिविधियों का सही विश्लेषण अतीत के संदर्भ को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत के वर्तमान संविधान पर स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की शासन-व्यवस्था की गहरी छाप है। इंग्लैण्ड का संविधान तो क्रमिक विकास का ही परिणाम है। परन्तु एक ही देश की विभिन्न कालों की राष्ट्रीय सरकारों तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में शत-प्रतिशत समानता नहीं मिल सकती, इनमें थोड़ी-बहुत असमानता अवश्य मिलेगी। यदि इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो यह अम्बरात्तीय तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा।

(2) विश्व में प्रचलित विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना–भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और इंग्लैण्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदि देशों में भी है। संघात्मक सरकार अमेरिका में भी है, भारत, स्विट्जरलैण्ड, कनाडा आदि देशों में भी है। परन्तु दो देशों की राष्ट्रीय सरकारें कभी भी शत-प्रतिशत एकदूसरे के पूर्णत: समान नहीं होती। विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन को भी अम्बरात्तीय तुलना कहा जाता है। अधिक विचारकों ने तुलनात्मक शासन तथा राजनीति को राष्ट्रीय सरकारों तथा राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन बताया है और इसके अम्बरात्तीय तुलना स्वरूप के संबंध में यही धारणा सर्वमान्य है और इसी का अनुसरण करके राजनीतिशास्त्र के बहुत-से सिद्धान्त निष्कर्ष के रूप में निकाले गए हैं।

तुलनात्मक शासन तथा राजनीति के इस स्वरूप से स्पष्ट है कि इसके अन्तर्गत वर्तमान विश्व की राष्ट्रीय सरकारों, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन तो होता ही है, इसके साथ ही इसमें एक ही देश की विभिन्न कालों की राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन तथा एक ही देश की विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन तथा एक देश की विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन भी होता है।

तुलनात्मक शासन व राजनीति का विषयक्षेत्र
(Scope of Comparative Government and Politics)

तुलनात्मक शासन व राजनीति का विषयक्षेत्र क्या है, इसके बारे में काफी मतभेद हैं। इसके विषयक्षेत्र के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं:

1. कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण तथा
2. व्यवहारवादी दृष्टिकोण।

1. कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण (Legalistic or Institutional Viewpoint)–प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने इसके विषय क्षेत्र के संबंध में कानूनी अथवा संस्थागत दृष्टिकोण का समर्थन किया है। उनका कहना था कि तुलनात्मक शासन और राजनीति का अध्ययन कानून अथवा संविधान की सीमा के अन्दर होना चाहिएँ अर्थात् संविधान कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचना अथवा राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन ही इसका विषयक्षेत्र है। उनका कहना है कि संविधान के अन्तर्गत राजनीतिक संस्थाओं, जैसे कि कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका आदि की रचना, उनकी शक्तियों, कार्यों तथा संविधान द्वारा निश्चित किए गए राजनीतिक व्यवहार आदि के आधार पर ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिएँ अर्थात् उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक व्यवहार की तुलना की जानी चाहिए, जो कानून द्वारा निश्चित तथा मान्य हैं। इस प्रकार ये विचारक केवल राजनीतिक संस्थाओं की तुलना पर आधारित अध्ययन को ही तुलनात्मक शासन व राजनीति मानते हैं।

2. व्यवहारवादी दृष्टिकोण (Behavioural Viewpoint)–तुलनात्मक शासन व राजनीति के विषयक्षेत्र के संबंध में दूसरे दृष्टिकोण के समर्थकों का विचार है कि संविधान के अन्तर्गत स्थापित राजनीतिक संस्थाओं की तुलना से राजनीतिक व्यवहार को वास्तविक रूप नहीं समझा जा सकता। रूस में कानूनी दृष्टिकोण से लोकतंत्र है, परन्तु वास्तविक राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। इंग्लैण्ड में भी जो दिखाई देता है, वह वास्तविक रूप में नहीं है और जो वास्तविक रूप में है, वह दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी शासन-व्यवस्था के वास्तविक रूप का केवल कानून या संविधान की सीमा में बंधी संस्थाओं के अध्ययन से पता नहीं चल सकता है और इसीलिए शासन-व्यवस्थाओं की संस्थागत तुलना पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो सकती। राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करते हुए उन तथ्यों तथा कारकों की भी तुलनात्मक शासन व राजनीति के अन्तर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना आवश्यक है। अमेरिकन राष्ट्रपति कानूनी दृष्टि से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है। क्या अमेरिकन दलीय व्यवस्था के अध्ययन और उसकी किसी अन्य के बिना, जिसके

NEERAJ PUBLICATIONS